

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1939 (श0)

(सं0 पटना 673) पटना, सोमवार, 31 जुलाई 2017

सं० 08/आरोप-01-65/2015-7093/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प 12 जून 2017

श्री राजाराम चन्द्र राम, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक—1374/08, 1137/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी— सह—प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिस्फी, मधुबनी के विरूद्ध अवैध रूप से सैरातों की बंदोवस्ती करने एवं शिक्षक नियोजन में अनियमितता बरतने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक 15789 दिनांक 22.11.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

अनुशासिनक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र—ंक' एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि आरोप के एक अन्य मामले में निलंबित (विभागीय संकल्प ज्ञापांक 433 दिनांक 09.02.2009) रहने के बावजूद आरोपित पदाधिकारी द्वारा वक्फ बोर्ड के बगीचे की बंदोवस्ती हेतु कार्रवाई की गयी। उक्त बंदोवस्ती में भाग लेने वाले का हस्ताक्षर भी बीड सीट पर संदिग्ध पाया गया। इसके पश्चात जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त बगीचे की नये सिरे से बंदोवस्ती की गयी, जिसमें पूर्व में की गयी बंदोवस्ती से तीन लाख रूपये से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्री राम के विरूद्ध निलंबन अविध में कार्य करने एवं वित्तीय शक्तियों का गलत ढ़ंग से प्रयोग करते हुए राजस्व की क्षिति पहुंचाने संबंधी आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों पर श्री राम से प्राप्त लिखित अभिकथन एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा के उपरांत सम्यक विचारोपरांत संकल्प ज्ञापांक 3102 दिनांक 16.03.2017 द्वारा कालमान वेतन में निम्नतर दो प्रक्रम (दो वेतन वृद्धि पीछे) पर दो वर्षों के लिए संचयी प्रभाव से अवनित (दंड के प्रभाव अविध में वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करेंगे) का दंड संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरुद्ध प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक 22.04.2017) में श्री राम ने यह उल्लेख किया कि उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ आम में मंजर लगने के समय वक्फ बोर्ड के बगीचे की बंदोवस्ती की थी परन्तु चार माह बाद पुनः बंदोवस्ती कराये जाने पर राजस्व में वृद्धि होना स्वभाविक था। आरोप के अन्य बिन्दुओं पर श्री राम ने कोई बचाव प्रस्तुत नहीं किया।

पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर विचार करते हुए यह पाया गया कि श्री राम ने निलंबन अवधि में आनन—फानन में त्रुटिपूर्ण बीड सीट पर बन्दोवस्ती करने संबंधी प्रमाणित आरोपों के बचाव में कोई तथ्य नहीं दिया है। इसके साथ ही अभ्यावेदन में प्रस्तुत तर्क से उनके निर्दोष होने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार श्री राम के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री राजाराम चन्द्र राम, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक—1137/11, के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3102 दिनांक 16.03. 2017 द्वारा संसूचित दंड यथावत रखा जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, बिहार गजट (असाधारण)673-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in